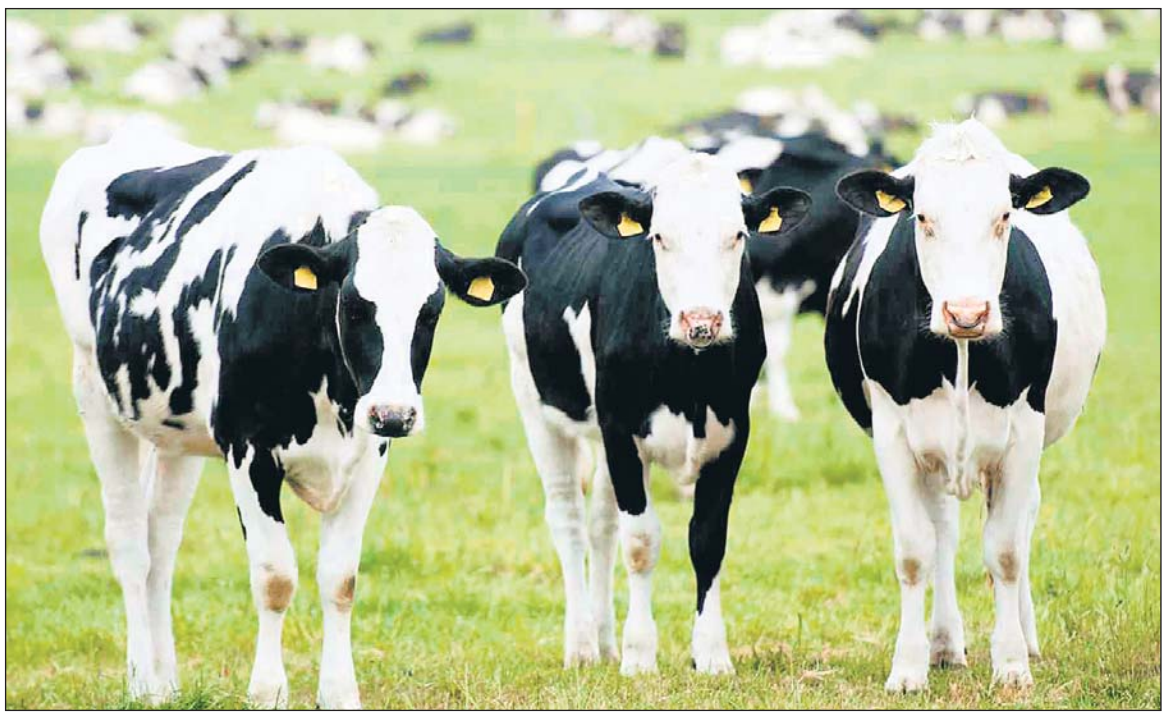

न्यूजीलैण्ड की सरकार ने गायों की डकार पर भारी भरकम टैक्स वसूलने की घोषणा की है। इसके पीछे सरकार का मकसद ग्रीन हाउस गैसों के उर्त्सजन को कम करना है। सरकार एवं पर्यावरविदों का मानना है कि, गायों एवं मवेशियों की डकार से "मीथेन" गैस निकलती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है। सरकार की इस योजना से न्यूजीलैण्ड के किसान सकते में आ गये हैं और बृहस्पतिवार को इसके खिलाफ बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए। "ग्राउण्ड स्वैल न्यूजीलैण्ड" समूह की मदद से देशभर के कस्बों और शहरों में 50 से अधिक जगहों पर विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। पिछले सप्ताह सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की योजना के तहत नया कृषि टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था। इसमें गाय की डकार पर टैक्स लगाने की योजना भी शामिल है। न्यूजीलैण्ड में कृषि से सबसे अधिक लोग जुड़े हैं। देश की आबादी करीब 50 लाख है लेकिन इसकी तुलना में यहां एक करोड़ से अधिक गाय और भैंसें हैं और 2.6 करोड़ भेड़ें हैं। देश में समस्त ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा खेतों से आता है जिसमें मवेशियों की डकार से निकलने वाली मीथेन विशेष रूप से बड़ा योगदान देती है। वैलिंगटन में विरोध प्रदर्शन के दौरान डेव मैककर्डी नामक किसान ने कहा कि, ज्यादातर किसानों ने साल भर, विशेष रूप से वसंत ऋतु के दौरान अपने खेतों में कड़ी मेहनत की है, सरकार को इस योजना पर विचार करना चाहिए। न्यूजीलैण्ड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने 2050 तक देश को कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाने की योजना बनाई है। इस योजना में 2030 तक खेतिहर जानवरों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन को 10 प्रतिशत और 2050 तक 47 प्रतिशत तक कम करना शामिल है।

'काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर आती नहीं'

जयपुर में खड़गे का बहिष्कार करने वाले धारीवाल, जोशी और राठौड़ दिल्ली में बधाई देने पहुंचे, तो दिव्या मदेरणा ने तंज कसा

जयपुर, 20 अक्टूबर (का.प्र.)। इसे समय का फेर ही कहेंगे, 25 सितंबर को जब मल्लिकार्जुन खड़गे पर्यवेक्षक के रूप में कांग्रेस विधायक दल की बैठक लेने जयपुर आए थे, तब संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल अपने घर पर विधायक दल की समानांतर बैठक कर रहे थे। उस बैठक में महेश जोशी भी मौजूद थे और धर्मेन्द्र राठौड़ भी। ये नेता खड़गे और प्रभारी अजय माकन द्वारा बुलाए जाने के बावजूद अधिकृत बैठक का बहिष्कार कर विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे दे रहे थे।

अब जब खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए हैं तो यह नेता लाइन लगाकर उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हो गए। इन नेताओं ने बधाई देने वाले फोटो को पोस्ट करके कांग्रेस विधायक और पूरे प्रकरण में लगातार धारीवाल तथा महेश जोशी पर तंज कसने वाली दिव्या मदेरणा ने फिर इन नेताओं पर कटाक्ष किया और कहा कि "काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर आती नहीं।"

- **खड़गे को बधाई देने वाले इन नेताओं के फोटो के साथ मदेरणा ने लिखा है कि, हाई कमान के खिलाफ साजिश करने वाले लोग सबसे पहले कांग्रेस के नए अध्यक्ष को बधाई देने दिल्ली गए।**
- **गौरतलब है कि 25 सितम्बर को जब राज्य विधायक दल की बैठक मु.मंत्री आवास पर होनी थी, तब एक समानान्तर बैठक धारीवाल के घर बुलाई गई थी और ये नेता अधिकृत बैठक लेने आए पर्यवेक्षक खड़गे की बैठक में नहीं पहुंचे थे।**

दिव्या मदेरणा ने ट्वीट करके तीनों नेताओं के खड़गे को बधाई देने वाला फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि "काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुम को मगर नहीं आती। मतलबी दुनिया के रंग हैं। बैरंग लौटाने वाले रंगीन फूलों का गुलदस्ता देते हुए। यह तो सर्वोच्च अवसरवाद की श्रेणी में ही आता है।"

इससे एक दिन पहले ही दिव्या मदेरणा ने ट्वीट किया था कि हाईकमान के खिलाफ साजिश वाले लोग सबसे पहले हैं, जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष को बधाई देने दिल्ली गए हैं। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने जयपुर भेजे गए आब्जर्वर में एक खड़गे ही थे, जिन्होंने बाद में अनुशासन समिति को एक लिखित रिपोर्ट सौंपी और जिसके आधार पर नोटिस जारी हुए।

दरअसल खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के मौके पर उन्हें बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली गए, उनके खास माने जाने वाले मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आर.टी.डी.सी. के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी खड़गे को बधाई देने दिल्ली गए। इन्हीं तीनों पर 25 सितंबर को बुलाई गई विधायक दल के समानांतर अलग रूप से विधायकों की बैठक बुलाने और आलाकमान के आदेशों की अवहेलना का आरोप है। खड़गे को बधाई देने के लिए इन नेताओं के दिल्ली पहुंचने के बाद ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा ने एक बार फिर ट्वीट किया।

दिव्या मदेरणा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक समय वो जब खड़गे जी इंतजार करते रहे, उनसे मिलने नहीं आए। आज समय बदला तो सबसे पहले पहुंचे हैं। दिव्या ने लिखा कि यह समय-समय की बात है। विधायक ने ट्वीट में जो फोटो लगाई उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर नहीं आ रहे हैं।

विधायक दिव्या मदेरणा ने एक के बाद एक तीन ट्वीट करते हुए इन तीन नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हाईकमान के खिलाफ साजिश वाले लोग सबसे पहले हैं, जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष को बधाई देने दिल्ली गए हैं। संयोग से खड़गे ही विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने जयपुर भेजे गए पर्यवेक्षकों में से एक थे। जिन्होंने बाद में अनुशासन समिति को एक लिखित रिपोर्ट सौंपी। जिसके आधार पर नोटिस जारी हुए।

इससे पहले दिव्या ने ट्वीट कर कहा कि कभी घमंड न कीजिए, समय बड़ा बलवान, किए रंक राजा कई, निर्धन को धनवान। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने 25 सितंबर की घटना के साथ जोड़ कर लिखा कि उस दिन खड़गे जी के बुलाने पर नहीं आए। विधायक दल की मीटिंग को बॉयकॉट कर समांतर मीटिंग की थी। यही मुख्य सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री ने खड़गे जी के सामने शर्त रखी कि जो फ़ैसला होगा वह 19 अक्टूबर के बाद होगा व हम सिर्फ सोनिया गांधीजी से मिलेंगे।

भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में आज

राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा एवं संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष बैठक लेंगे

जयपुर, 20 अक्टूबर। प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा को लेकर भाजपा पूरे एक्टिव मोड में है। इसी के लिए प्रदेश में भाजपा के केंद्रीय नेताओं के दौरे लगातार हो रहे हैं। भाजपा के आगामी कार्यक्रमों को देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदेश कोर कमेटी के सभी नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रदेश भाजपा संगठन में आंतरिक कलह और समन्वय की कमी के बारे में चर्चा की जाएगी।

इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 नवम्बर को राजस्थान में मानगढ़ धाम आने के कार्यक्रम तथा जयपुर में बड़ी सभा के आयोजन से सम्बंधित रणनीति पर चर्चा की जाएगी। भाजपा में आने वाले एक दर्जन नेताओं के मसले के साथ अन्य विषयों पर चर्चा होने के संकेत हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सहयोग नहीं मिलने के कारण कोटा संभाग में 20 और 21 अक्टूबर को आयोजित बूथ सम्मेलन को स्थगित करने के मामले को गंभीर माना गया है।

जेपी नड्डा इस बात से भी नाराज है कि प्रदेश में भाजपा के संगठन स्तर पर होने वाले आयोजन में आम लोगों का जुड़ाव कम है, ऐसे में वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में पार्टी कैसे सत्ता में आएगी, इस पर भी खुलकर बातचीत होगी और रणनीति तैयार की जाएगी।

प्रदेश में कुछ महीने से भाजपा के नेताओं में समन्वय की भारी कमी है और अलग-अलग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे है इससे यह प्रदर्शित हो रहा है कि पार्टी के नेताओं में एकता नहीं है। इस स्थिति को लेकर ही राष्ट्रीय नेतृत्व गंभीर है।

गौरतलब है कि कोर कमेटी की यह बैठक कोटा में आयोजित होने वाली थी लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को हिमाचल में चुनाव होने के कारण प्रदेश के नेताओं को दिल्ली बुलाकर चर्चा की जाएगी।

कोर कमेटी की बैठक में प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चन्द्र शेखर,उपाध्यक्ष एवं सांसद सी.पी.जोशी, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रतिपक्ष नेता कटारिया, उपनेता राठौड़ सहित 11 सदस्य एवं संगठन महामंत्री बीएल संतोष, महामंत्री एवम प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के बैठक में मौजूद रहने की संभावना है।

- **इस बैठक में प्रदेश कोर कमेटी के सभी नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रदेश भाजपा संगठन में आंतरिक कलह और समन्वय की कमी के बारे में चर्चा की जाएगी।**
- **बैठक में भाजपा में शामिल होने के इच्छुक एक दर्जन नेताओं के मसले के साथ अन्य विषयों पर चर्चा होने के संकेत हैं।**
- **बताया जा रहा है कि, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का सहयोग नहीं मिलने के कारण कोटा संभाग में 20 और 21 अक्टूबर को आयोजित बूथ सम्मेलन को स्थगित करने के मामले को गंभीर माना गया है और इस पर भी चर्चा होगी।**

चैरिटी संस्थाओं पर आयकर

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की एक बैंच ने चैरिटी संस्थाओं पर आय कर लगाकर विवादो का पिटारा खोल दिया है। बैंच ने व्यवस्था दी कि ये संस्थाएँ किसी भी तरह से यदि किसी व्यापार, वाणिज्य अथवा कारोबार में संलग्न हो जाती हैं तो फिर वे कर में छूट की मांग नही कर सकती।

बैंच ने यद्यपि वर्ष 2009 व उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट में जोड़े गए संशोधन की सहायता ली और उल्लेख किया कि यदि किसी संस्था के लाभ कुल प्राप्तियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होते हैं तो उस पर कर नही लगाया जाएगा।

बैंच ने उदाहरण के तौर पर गुजरात और राजस्थान की क्रिकेट एसोसिएशन्स के विरूद्ध अपीलों पर गुजरात तथा राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णयों को खारिज कर दिया और संबंधित प्राधिकरणों से कहा कि वे टैक्स मुद्दे को नए सिरे से तय करें।

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, चैरिटी ट्रस्ट अगर किसी भी प्रकार के व्यवसाय या व्यापार में लिप्त हैं तो उन्हें आयकर छूट नहीं मिल सकती।**

कोर्ट, आकलन करने वाले प्राधिकरणों को वार्षिक आधार पर संस्थाओं के रिकॉर्ड का सूक्ष्म परीक्षण करने का निर्देश देता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि संस्था की गतिविधियां व्यापार, वाणिज्य या कारोबार की श्रेणी में आती है। उन्हें यह भी परीक्षण करना है कि धारा 2 (15) के तहत समय-समय पर संशोधित अधिकतम सीमा का क्या उल्लंघन किया गया है और क्या उन्हें छूट का लाभ नहीं नहीं देना हैं।

राहुल असली....

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इतिहास में, चुनाव कराना केवल छः बार ही आवश्यक महसूस किया गया है, क्योंकि इन छः बार की स्थितियों के अलावा, चुनाव में खड़ा होने के लिये कोई दूसरा उम्मीदवार होता ही नही था, तथा इसलिए एक ही व्यक्ति निर्विरोध निर्वाचित घोषित होता रहता था।

पंकज शर्मा ने कहा है कि यद्यपि कांग्रेस अध्यक्ष पद के इस चुनाव में, गांधी परिवार ने किसी को अपना नामित उम्मीदवार नहीं बताया था, लेकिन ऐसा वातावरण जरूर बना दिया गया था कि खड़गे पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं। शर्मा ने कहा कि इस स्थिति में खड़गे के प्रतिद्वन्द्वी तथा चुनाव में 1,072 वोट प्राप्त करने वाले शशि थरूर ने बड़ा काम करते हुये, यह दर्शा दिया है कि पार्टी में आन्तरिक लोकतन्त्र मजबूत स्थिति में हैं।

उन्होंने कहा कि खड़गे पार्टी अध्यक्ष भले ही निर्वाचित हो गये हैं लेकिन कांग्रेस का भविष्य तो संगठन की अन्दरूनी नियुक्तियों पर ही निर्भर करेगा।

उन्होंने कहा कि राहुल ने ठीक ही कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी का सर्वोच्च पदाधिकारी है जिसके निर्देशन में वे (राहुल) काम करेंगे, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि राहुल पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और रहेंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से उनका कद और ऊँचा होगा।

आई.बी. ने खरीदा...

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गुप्तचर एजेंसी "इन्टेलीजेंस ब्यूरो" (आई.बी.) ने अप्रैल 2017 में इजरायली कंपनी "एन.एस.ओ. ग्रुप" से 3,15,000 डॉलर (उस समय 2 करोड़ रू. से अधिक) की कीमत का पैगसस स्पाइवेयर में लगे यंत्र से मिलता-जुलता हार्डवेयर खरीदा था। यह पैकिंग, जिस पर "रक्षा एवं सैन्य उपयोग के लिये" अंकित था, हवाई जहाज से दिल्ली पहुँची थी। यह समाचार "ऑर्गनाइज्ड क्राइम एण्ड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजैक्ट (ओ.सी.सी.आर.पी.) द्वारा जारी एक रिपोर्ट पर आधारित है। ओ.सी.सी.आर.पी. की रिपोर्ट, उसके द्वारा एकत्रित उस इम्पोर्ट डाटा पर आधारित थी, जिसमें द न्यूयॉर्क टाइम्स के इस दावे का सहारा लिया गया था कि भारत ने उस साल एक बड़े रक्षा-सौदे के अन्तर्गत, पैगसस खरीदा था। ओ.सी.सी.आर.पी. के अनुसार, इम्पोर्ट डेटा बताता है कि 18 अप्रैल, 2017 को आई.बी. को एन.एस.ओ. से हार्डवेयर का एक सामान प्राप्त हुआ, जो, "उस साज़-सामान के विवरण से मिलता-जुलता था, जिसे अन्य स्थानों पर पैगसस सॉफ्टवेयर को चलाने के काम में लिया जा रहा था।" यह सामान हवाई जहाज से लाया गया था तथा दिल्ली में उतारा गया था। ओ.सी.सी.आर.पी. का कहना है कि वह इस डेटा तक एक "सब्सक्रिप्शन-बेस्ड ट्रेड" वैबसाइट के जरिये पहुँचा था। इस वैबसाइट पर पूरी दुनिया के वाणिज्यिक सामानों के आयात-निर्यात का विवरण उपलब्ध है।

ब्रिटेन की..

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बजाए उस सिंगल पार्टी के जो शीर्ष पद पर एक के बाद एक उम्मीदवार को बैठा रही है। लेबर पार्टी के नेताओं ने इस स्थिति को शीर्ष पद के लिए एक "रिवॉल्विंग डोर" की संज्ञा दी है जिसमें एक व्यक्ति प्रवेश कर रहा है और दूसरा गिर रहा है। इसके बावजूद, आम चुनाव का निर्णय करने का काम सरकार का है तथा उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। सत्तारूढ़ कंज़रवेटिव्ज़ के एक भी गुट को वर्तमान स्थिति में सत्ता में वापसी करने की दूर-दूर तक उम्मीद नहीं है, तथापि पार्टी बड़ी व्याकुलता से इसका समाधान अपने भीतर ही ढूंढ़ने की कोशिश कर रही है। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो किंग चार्ल्स तृतीय के पास अपने राज्याभिषेक से पूर्व ही नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का मौका होगा। यह फिर शायद शताब्दियों में एक नई नज़ीर बन जाएगा।

सैन्य सेवा कर्मी ...

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कहा याचिकाकर्ता के पिता सैन्य सेवा के असैनिक कर्मचारी हैं और वे भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के सैनिक नहीं हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता को सैनिक स्कूल में सैनिक कोटे का लाभ नहीं दिया जा सकता। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश प्रियांशी की ओर से अपने पिता के जरिए दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के पिता के सेवा प्रमाण पत्र में कोई रैंक भी नहीं बताई गई है, जिससे साबित होता है कि वह सेना के किसी भी अंग में कोई सैन्य पद नहीं रखते हैं।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा-2022 पास की थी। इसके अलावा मेडिकल टेस्ट में पास होने के बाद उसका नाम मेरिट लिस्ट में भी आ गया था। वहीं दस्तावेज सत्यापन के समय उसे यह कहते हुए सैनिक कोटे का लाभ देने से इनकार कर दिया कि उसके पिता सैनिक की श्रेणी में नहीं आते हैं। याचिका में कहा गया कि उसके पिता आयुध डिपो, आगरा में कार्यरत हैं। इसलिए रक्षा मंत्रालय के अधीन आने के कारण उन्हें सैनिक की श्रेणी में मानकर याचिकाकर्ता को सैनिक कोटे का आरक्षण दिया जाए। इसका विरोध करते हुए केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया था कि भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के कार्मिकों को ही सैनिक माना गया है और रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले असैनिकों को सैनिक कोटे का आरक्षण नहीं दिया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

आंध्र प्रदेश में प्रवेश होते ही ...

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तरह सफाया ही हो गया है तथा तेलंगाना में, पार्टी संगठन अभी मौजूद है तथा अपनी मौजूदगी दर्शाने के लिये संघर्षरत है।

इस पृष्ठभूमि में, आंध्रवासियों ने भारत जोड़ो यात्रा का जिस जोश-खरोश से जबरदस्त स्वागत किया है, वह कांग्रेस और राहुल गांधी में पार्टी के पुनरोद्धार को लेकर निश्चित रूप से नई आशाएं पैदा करने वाला था। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि लोगों को भारत जोड़ो यात्रा तक पहुँचने से रोकने के लिये राज्य सरकार के बैरिकेड्स जनसमुदाय के जोश एवं उत्साह को कम करने में असफल रहे।

यात्रा में युवाओं और किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा और राज्य में जहां-जहां से राहुल गांधी पैदल जा रहे हैं, लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब हो रहे हैं, वास्तव में, यह उन लोगों के लिए एक सुखद आश्चर्य था जो अब भी पार्टी के साथ बने हुए हैं और कई लोग सिर्फ उनके दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े।

राहुल गांधी ने सही मुद्दे उठाए और केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के साथ किए गए अन्याय के बारे में बोला तथा वादा किया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वह अपनी सभी प्रतिबद्धताएं पूर्ण करेगी।

राजनीतिक विश्लेषक तेलुगु भाषी राज्यों में निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक तरह से थोड़ा-बहुत पुनरुद्धार देख रहे हैं, किन्तु क्या यह वास्तव में सही है।

आंध्र में जगनमोहन रेड्डी और तेलंगाना में टी.आर.एस. सुप्रीमो के. चन्द्रशेखर राव द्वारा अपने यहां से कांग्रेस का सफाया किए जाने के बाद इन राज्यों में पार्टी का पुनर्निर्माण करना खासतौर पर भारी काम है।

नालसर हैदराबाद के राजनीतिक विश्लेषक हराती वेगसान ने कहा कि "तेलंगाना में भाजपा चुनाव मैदान में बढ़त बनाने का ढोल पीट रही है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, यहां कांग्रेस आश्चर्य चकित करने जा रही है। उसके पास रेवंत रेड्डी के रूप में एक अच्छा नेता है और वह अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। हां के.सी.आर. अब भी सशक्त हैं, लेकिन सत्ता विरोधी जो भी भावनाएं हैं, उन्हें देखते वह कांग्रेस ही है जो भाजपा द्वारा बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने और भारी धनराशि झोंकने के बावजूद लाभ में रहने वाली है।"

एक अन्य राजनीतिक विश्लेषक ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि भाजपा में नेतृत्व का अभाव है और उसे कुछ और वर्षों तक अपने जनाधार को लेकर काम करने की जरूरत है। उसके बाद ही वह महत्वपूर्ण राजनीतिक बढ़त प्राप्त करने की उम्मीद कर सकती है। उन्होंने कहा कि "हां! वर्ष 2019 में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वर्तमान में स्थिति बिल्कुल ही अलग है, खासतौर पर भाजपा के संदर्भ में। स्थानीय नेतृत्व की पहचान करने और उसे खड़ा करने में भाजपा की विफलता ही वह कारण है कि वह अपनी संभावनाओं को पूरी तरह भुना नहीं सकेगी।"

दिवाली पर 75 हजार लोगों को रोजगार देगी मोदी सरकार

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान-रोजगार मेला - का शुभारंभ करेंगे। समारोह के दौरान 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। देश भर से चयनित नये कर्मियों को 38 मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जा रहा है। ये राजपत्रित और गैर राजपत्रित समूहों के अलावा केंद्रीय सशस्त्र बलों में उप-निरीक्षक, कांस्टेबल, एल.डी.सी., स्टेनो, पी.ए., आयकर निरीक्षक, एम.टी.एस. तथा अन्य पदों के लिए चयनित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के मुताबिक इस उपलक्ष्य में 22 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे आयोजित कार्यक्रम में मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे।

अडानी व अंबानी नहीं, देश के सबसे बड़े दानवीर हैं शिव नादर

एक सर्वे के मुताबिक एच.सी.एल. के फाउण्डर नादर ने 2022 में 1161 करोड़ रु. दान किये हैं

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। देश के सबसे बड़े दानवीर अरबपतियों की सूची में शिव नादर सबसे आगे हैं। एडलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रॉपी लिस्ट 2022 के मुताबिक आई.टी. कंपनी एच.सी.एल.के फाउंडर शिव नादर ने 1,161 करोड़ रुपये रुपये वार्षिक दान दिए हैं। इस हिसाब से कह सकते हैं कि शिव नादर ने हर दिन 3 करोड़ रुपये दान के लिए खर्च किए हैं।

इसी के साथ शिव नादर ने आई.टी. कंपनी विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी को पछाड़ दिया है। अब तक अजीम प्रेमजी को सबसे बड़ा दानवीर माना जाता था। हालांकि, इस साल अजीम प्रेमजी ने 484 करोड़ रुपये का वार्षिक दान दिया है और वह सूची में दूसरे स्थान पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला हैं। अंबानी ने एक साल में 411 करोड़ रुपये का दान दिए और इसी अवधि में बिड़ला ने 242 करोड़ रुपये का दान दिया।

आई.टी. सेक्टर की दिग्गज कंपनी माइंडट्री से जुड़े सुष्मिता और सुब्रतो बागची के अलावा राधा और एन.एस. पार्थसारथी 213 करोड़ रुपये के वार्षिक दान के साथ पांचवें स्थान पर हैं। इसी तरह, 190 करोड़ रुपये के दान के साथ गौतम अडानी इस साल सूची में सातवें स्थान पर थे। बता दें कि गौतम अडानी देश के सबसे रईस अरबपति हैं।

वहीं, आई.टी. कंपनी इंफोसिस से जुड़े नंदन नीलेकणि, क्रिस गोपालकृष्णन, और एस.डी. शिबूलाल ने क्रमशः 159 करोड़ रुपये, 90 करोड़ रुपये और 35 करोड़ रुपये दान के लिए खर्च किए हैं। इनकी रैंकिंग क्रमशः 9, 16 और 28 वीं है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जेरोधा के 36 वर्षीय निखिल कामथ एडेलगिव हुरुन परोपकार सूची 2022 में सबसे कम उम्र के परोपकारी व्यक्ति हैं। उन्होंने और उनके भाई नितिन कामथ ने इस वर्ष अपने दान को 300 प्रतिशत बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया।

मुलायम सिंह ...

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

है, भले ही वे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव क्यों न लड़ें। ज्ञातव्य है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, सपा से अलग हुये शिवपाल-समर्थकों की पार्टी है। भाजपा के वार्ताकार पिछले कुछ दिनों से शिवपाल के सम्पर्क में है। इनका उद्देश्य किसी न किसी तरह शिवपाल को मैनपुरी चुनाव लड़ने के लिये तैयार करना है क्योंकि चुनाव मैदान में शिवपाल की मौजूदगी से यादव मतों का बँटना सुनिश्चित है।

जहाँ तक सपा-प्रमुख अखिेश यादव का प्रश्न है, उनके लिये तो मैनपुरी की लड़ाई "करो या मरो" की लड़ाई होगी क्योंकि मुलायम सिंह यादव की राजनैतिक विरासत का मुद्दा दाँव पर लगा होगा। इस सीट के लिये सपा के संभावित उम्मीदवारों में, अखिलेश की पत्नी डिम्पल या फिर उनके चचेरे भाई एवं पूर्व सांसद धर्मेन्द्र यादव शामिल हैं।

ममता बनर्जी एक बार फिर खुलकर सौरव गांगुली के समर्थन में आईं

'सौरव गांगुली को बी.सी.सी.आई. नहीं बनने दिया लेकिन सरकार को उन्हें आई.सी.सी. का चीफ बनाने के लिए पूरा समर्थन और प्रयास करना चाहिये

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर सौरव गांगुली का समर्थन करते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान का बी.सी.सी.आई. प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया और उनकी जगह रोजर बिन्नी को अध्यक्ष बना दिया गया। गांगुली को 19 नवंबर, 2019 को बी.सी.सी.आई. अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पिछले दिनों रोजर बिन्नी को नया अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कहा कि आपने सौरव गांगुली को हटा दिया गया, लेकिन जय शाह को बरकरार रखा।

- **उन्होंने कहा कि आपने सौरव गांगुली को हटा दिया गया, लेकिन जय शाह को बरकरार रखा।**
- **बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान का बी.सी.सी.आई. प्रमुख के रूप में कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया और उनकी जगह रोजर बिन्नी को अध्यक्ष बना दिया गया।**

हाल ही में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौरव गांगुली को अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आई.सी.सी.) भेजने की अपील की थी. गुरुवार को भी उन्होंने दोहराया कि गांगुली को बी.सी.सी.आई. प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल से वंचित किया गया था और कहा, "उन्हें आई.सी.सी. चुनाव लड़ने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? उन्होंने पद खाली रखा है ताकि कोई इसे लड़ सके। यह सौरव के लिए बहुत अनुचित है। वह दुनिया भर में जाने जाते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "सौरव बहुत हकदार थे। उन्होंने देश को गौरवान्वित किया था। उन्हें वंचित करने का कारण क्या है? पद किसी और के लिए रखा जा रहा है। मैं इसका कारण जानना चाहती हूं। अगर सचिन तेंदुलकर होते तो मैं उनका भी समर्थन करती। सिर्फ इसलिए कि वह एक विनम्र व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह इससे आहत हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908